विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	उद्यान विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	1261
उत्तर की तिथि	18–09–2020
विषय	परियोजनाएं
प्रश्नकर्त्ता का नाम	श्री नरेन्द्र बरागटा (जुब्बल–कोटखाई)
सम्बन्धित मंत्री	जल शक्ति मंत्री।

प्रश्न	उत्तर
(क) गत तीन वर्षो में दिनांक 31.07.2020 तक उद्यान विभाग के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा चलाई गई परियोजनाओं में क्या–क्या कार्य हुए;	हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत किए गये कार्य का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।
(ख) इन परियोजनाओं के कार्य की गुणवता हेतु जांच हुई है; यदि हां, तो इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और	यह मद परियोजना से सम्बन्धित नहीं है।
(ग) इन परियोजनाओं पर विश्व बैंक ने कोई आपत्ति जताई है; ब्यौरा दें?	जी, नहीं। परियोजना के अंतर्गत सभी कार्यो का कियान्वयन विश्व बैंक की स्वीकृति के बाद ही किया जा रहा है।

(क) हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में किए गये कार्यों की नवीनतम स्थिति

हिमाचल प्रदेश उच्च मूल्य वाले विभिन्न कृषि उत्पादो की अपार सम्भावनाओं के लिए जाना जाता है जिनमें जलवायु में विभिन्नता, बे–मौसमी फल–फसलों को उगाने एवं विपणन की सम्भावनायें, उच्च तकनीकी जानकारी रखने वाले कृषक एवं सीमावर्ती उपभोक्ता बाजार से अपेक्षाकृत नजदीकी शामिल है। राज्य के बागवानी उद्योग के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए बागवानी के विकास हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा विश्व बैंक पोषित 'हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना' परिकल्पित की गई। इस परियोजना का उद्धेश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो कृषि समुदाय को तकनीकी क्षमता हासिल करने और बाजार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है तथा राज्य में बागवानी क्षेत्र में कमियों को दूर करने के उपाय सुझाना व इस क्षेत्र को अधिक उत्पादक, सक्षम तथा लाभ अर्जित करने वाला क्षेत्र बनाना है। परियोजना का प्रयास उच्च मूल्य बागवानी उत्पादन में विविधीकरण से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भारत और प्रदेश सरकार की दीर्घकालिक नीतियों तथा व्यापक बृद्धि व विकास से सम्बद्ध मुख्य उद्धेश्यों को प्राप्त करना भी है।

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना जो कि अगस्त 2016 से प्रभावी है, का मुख्य उद्देश्य "चयनित बागवानी उत्पादों की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा विपणन में सुधार करके लघु एवम सीमांत किसानो व बागवानो तथा कृषि से जुड़े व्यवसायिओं को सहयोग देना" है ।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत किए गये कार्यकलापों की अद्यतन स्थिति निम्न है :-

1. बागवानी उत्पादन एवं विविधिकरण–

- परियोजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों में 16.44 लाख उच्च गुणवत्ता वालें सेब, नाशपति, चैरी, पलम, आडू तथा अखरोट की किस्मों के पौधों एवं मूलवृन्तो का आयात किया गया।
- आयातित पौधों को लगभग 310 शीतोष्ण क्षेत्र क्लस्टर में किसानों को बांटा गया। इसके अतिरिक्त आयातित पौधों कों विश्वविद्यालय एवं विभाग के 26 फल संतति एवं प्रदर्शन केन्द्रों में रोपित किया गया जिसमें से 19 संतति केन्द्रों पर वड वुड बैंक की स्थापना की गई तथा 8 बागीचों में प्रदर्शन स्थल तथा 11 जगहों पर क्लोनल रूट स्टॉक के मदर प्लांट की स्थापना की गई।
- किसानों को उच्च घनत्व के बागीचों की स्थापना तथा प्रबंधन की जानकारी हेतु डॉ यशवंत सिंह परमार औद्योनिकि एवं वानिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा एडहोक पैकेज ऑफ प्रेक्टिसज (adhoc package of practices) बनाई गई

है तथा इस कार्य को अन्तिम रूप देने हेतु विभिन्न पहलूओं पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

- प्रदेश में बागवानी के विकास हेतु दो उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। इन केन्द्रों की स्थापना हेतु शिलारू तथा पालमपुर में कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त जिलों में लगभग 500 अधिकारियों को परियोजना के विभिन्न घटकों व गतिविधियों की जानकारी हेतु जिला स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से अवगत करवाया जा चुका है।
- प्रदेश में फलों की उत्पादकता में सुधार तथा विविधिकरण को बढ़ावा देने हेतु अंतराष्ट्रीय स्तर के 10 विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा रही हैं जो कि पौधशाला प्रबंधन, फल फसल प्रबंधन तथा जल प्रबंधन हेतु अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों द्वारा अभी तक विभाग के लगभग 500 तकनीकी कर्मचारियों को Canopy and Floor Management में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेषज्ञों द्वारा लगभग 2500 बागवानों व प्रूनरों को शीतोषण फलों की छंटाई एवं फ्लोर प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा लगभग 33 विभागीय तकनीकी अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में नर्सरी व बागीचे के प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया गया है।
- डॉ यशवंत सिंह परमार औद्योनिकि वानिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 145 तकनीकी अधिकारी तथा लगभग 400 किसानों को सघन तथा मध्यम घनत्व सेब की खेती के बारे में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 50 प्रूनेरों को सघन बागीचों की काट छाँट तथा 25 विभागीय दक्ष मालियों को अखरोट की chipbudding के संन्दर्भ में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मशोबरा तथा बजौरा में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा परागण प्रबंधन पर लगभग 435 बागवानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- विभागीय अधिकारियों को राज्य से बाहर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है जिसमें 57 अधिकारियों को सेब की उच्च एवं मध्यम घनत्व की खेती की जानकारी हेतु श्रीनगर तथा 25 अधिकारियों को आम, अमरुद तथा नींबू प्रजाति के फलों की खेती की जानकारी हेतु पुणे भेजा गया।
- इस परियोजना को सभी जिलों में सुचारू रूप से चलाने हेतु उन क्षेत्रों/क्लस्टरों का चयन किया गया जहाँ बागवानी आधारित विविधिकरण की अधिक संभावनाएं हैं। आरंभिक तौर पर चिन्हित क्लस्टरों में जहाँ लोगों की सहमति एवं सहभागिता अधिक मिल रही है उन्हीं चयनितक्षेत्रों में वाटर यूजर

ऐसोसिएशन बनाई जा रही है ताकि उनकी सहभागिता से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सके।

- गत तीन वर्षों में परियोजना में लगभग 3500 किसानों को 2.00 लाख उन्नत किस्म के फल पौधे (सेब, अखरोट, चैरी, नाशपाती, आदि) क्लस्टर के बागवानों में वितरित किए गए हैं।
- परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 153 जल उपयोग कर्ता संघ(WUA) बन चुके हैं तथा 108 जल उपयोगकर्ता संघ का पंजीकरण हो चुका है। अभी तक 59 जल उपयोग कर्ता संघ(WUA)को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जल उपयोग कर्ता संघ(WUA)का बनना, पंजीकरण तथा प्रशिक्षिण आगे भी जारी है।
- इस परियोजना के तहत 51 क्लस्टर(cluster)की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR)बन चुकी है। इनमें से 16 DPR'S की राशि 761.42 लाख रु0 जल उपयोग कर्ता संघ को आबंटित किया जा चुकी है तथा 4 जल उपयोग कर्ता संघ में कार्य आरम्भ हो चुका है।

2. बागवानी उत्पादों का मूल्य संवर्धन (Value addition) व कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देना–

- किसान उत्पादक समूहों का गठन तथा उनके द्वारा सामूहिक रूप से उपज का एकत्रीकरण व विपणन हेतु परियोजना के अन्तर्गत 30 किसान समूहों व सामुदायिक किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी । इन केन्द्रों पर किसान व बागवान अपनी उपज को सामूहिक रूप से ग्रेडिंग व पैकिंग करेंगे तथा उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रदेश व देश की मंडियों में विपणन की वयवस्था भी स्वयं करेंगे। बेसलाइन सर्वेक्षण व स्थानों का चयन का कार्य प्रारम्भ आरंभ कर दिया है। इसके अतर्गत प्रदेश में अब तक 390 सामान रूचि किसान समूह(CIG) बनाए गए जिनमें 7000 बागवानों का चयन किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत 30 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा जिसके लिए प्रारम्भिक तौर पर 390 समूह (CIG) तैयार कर लिए गए हैं।

- एच. पी. एम. सी के ग्रेडिंग पैकिंग, शीत भंडारण, सी ए स्टोर एवं विधायन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण व उन्नतीकरण किया जा रहा है।

- कोल्ड चेन परियोजना के अंर्तगत जिसमें मौजूदा वातानुकूलित शीतगृह व पैंकिग ग्रेडिंग हाऊसिस की कार्यक्षमता को बढ़ाना तथा नए पैकिंग ग्रैडिंग हाऊस और वातानुकूलित शीतगृह स्थापित करने का प्रावधान है। इस संदर्भ में रोहडू, गुम्मा (कोटखाई), तथा जडोल–टिक्कर में निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका हैं तथा ग्रैडिंग हाऊस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए LOA जारी कर दिया गया है

तथा टुटूपानी(शिमला) और भूंतर (कुल्लू) में निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए भी LOA जारी कर दिया गया है।

- इसके अतिरिक्त पैकिंग ग्रैडिंग हाऊसिस की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए ओडी (कुमारसेन) तथा पतलीकूहल (कुल्लू) के लिए LOA जारी कर दिया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त ज्ञाबुंग (किन्नौर) में नए पैंकिग ग्रैडिंग हाऊस स्थापित करने के लिए निविदा दस्तावेज विश्व बैंक की अंतिम स्वीकृती/सहमति के लिए भेज दी गई है, तथा रिकांगपिओं (किन्नौर) में वातानुकूलित शीतगृह प्रस्तावित हैं, जिसकी D.P.R. तैयार की जा रही है।
- जंजहैली/बुडेहरी (चच्योट) जिला मंडी तथा राजपूरा जिला चम्बा में नए पैकिंग ग्रैडिंग हाऊस और वातानुकूलित शीतगृह स्थापित करने के लिए भूमि का चयन कर दिया गया हैं, तथा इनके D.P.R. बनाने का कार्य प्रगति पर है।
- इसके अतिरिक्त फल विद्यायन संयंत्र ''पराला (ठियोग) शिमला में 18000 मिट्रिक टन, विद्यायन क्षमता वाला नया फल विद्यायन संयंत्र स्थापित करने के लिए दिनांक 10.09.2020 को वित्तिय निविदाएं खोली जानी है व परवाणू और जरोल फल विद्यायन संयंत्रो का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए निविदा दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त जाबली में फल पेय पदार्थो का विक्रय केंद्र बनना प्रस्तावित है, जिसके लिए निविदा दस्तावेज विश्व बैंक की स्वीकृति एवं सहमति के लिए भेज दिया गया हैं।

- प्रदेश में बागवानी आधारित व्यवसायों को बढावा देने हेतु बागवानों व उद्यमियों को प्रशिक्षण व सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चयनित सेवा प्रदाता के साथ इस गतिविधि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में जिला मंडी, कांगडा व सोलन में बागवानी उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है । बागवानी उद्यमियों से बागवानी आधारित व्यवसाय स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच प्रक्रिया के पश्चात लगभग 60 बागवान उद्यमियों की साध्यता रिपोर्ट बन चुकी है व अनुदान (matching grant) प्रदान करने हेतु समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

3. कृषि उपज मंडियों का आधुनिकीकरण व विपणन सुविधाओं को विकसित करना

- इस घटक का मुख्य उद्देश्य किसानों व बागवानों को उच्च स्तरीय विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
- इसके अंतर्गत 5 मार्किट यार्ड (शाट, पालमपुर, कांगनी, पौंटा और परवाणू) के आधुनिकीकरण पर काम शुरू कर दिया गया है। पराला और महंदली मार्केट यार्ड के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।
- बंदरोल व शिलारू की डीपीआर तैयार की जा रही है।

4. परियोजना प्रबंधन -

- बागवानी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए किसानों के लिए ई–उद्यान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत मोबाइल एप्लिकेशन (Android:eudyan himachal) के साथ वेबसाइट (www.eudyan.hp.gov.in) को सार्वजनिक उपयोग के लिए लॉन्च किया गया है।
- उद्यान विभाग के निदेशालय, जिला व खंड स्तर के कार्यालयों को सूचना व संचार प्रौद्याोगिकी प्रणाली से जोड़ने हेतु पहले चरण के क्षेत्र की स्थापना के लिए हार्डवेयर वितरण कर दिया गया है। (662 डेस्कटॉप, 665 यूपीएस, 423 टेबलेट्स और 539 एमएफ प्रिंटर) परियोजना के लिए वेबसाइट विकसित करने का कार्य लगभग पूरा कर दिया है।
- सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विभिन्न जिलों में विभाग के लगभग 600 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।